



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2007/आश्विन 3, 1929

No. 282]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2007/ASVINA 3, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2007

विषय : मलेशिया, थाइलैंड, चीन तथा कोरिया जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 14" तथा 21" (समतल) आकार वाली कैथोड रे कलर पिकचर ट्यूबों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/8/2006-डी जी ए डी.—मै. सैमटेल कलर लि. ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारणार्थ) नियम, 1995 के अनुसार मलेशिया, थाइलैंड तथा चीन (14" तथा 21" आकारों के लिए) और कोरिया जन. गण. (21" के लिए) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 14" तथा 21" (समतल) आकारों वाली कैथोड रे कलर पिकचर ट्यूबों के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और पाटनरोधी जांच शुरु करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

2. विचाराधीन उत्पाद.—वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 14" तथा 21" (समतल) आकारों [उदाहरणार्थ 21" समतल प्रकार तथा 14" परम्परागत] वाली कैथोड रे कलर पिकचर ट्यूब्स हैं। कथित रूप से कैथोड रे कलर पिकचर ट्यूबों का विनिर्माण विभिन्न आकारों

में होता है। यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादों को उनकी ट्यूबों की समतलता के आधार पर बल्ब प्रकार (अर्द्ध समतल/पूर्णतः वर्गाकार सहित), फ्लैट ट्यूबों तथा वास्तविक समतल या समतल पतली ट्यूबों में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। अंततः वे उल्लिखित रूप से 50, 60 या 100 हर्ट्ज की बारंबारता के अंतर्गत प्रचालन करती हैं। इन उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से रंगीन टेलीविजन सेटों में होता है।

संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 की उपशीर्ष सं. 8540.11 के अंतर्गत आती है। सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

3. घरेलू उद्योग की स्थिति.—आवेदन मै. सैमटेल कलर लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच के संगत सूचना प्रस्तुत की है। जे सी टी इलेक्ट्रॉनिक्स लि., बी पी एल डिस्प्ले डिवाइसेस लि. तथा हॉटलाइन सी पी टी लि. द्वारा भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जाता है। याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। याचिकाकर्ता कंपनी का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। जांच के बाद प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार वैधता के मानदण्ड को पूरा करता है।

4. शामिल देश.—मलेशिया, थाइलैंड तथा चीन (14" तथा 21" दोनों के लिए) और कोरिया जन. गण. (21" के लिए) से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। अतः वर्तमान जांच में शामिल देश मलेशिया, थाइलैंड तथा चीन (14" तथा 21" दोनों के लिए) और कोरिया जन. गण. (21" के लिए) हैं (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है।)

5. **समान वस्तु.**—याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु दोनों समान वस्तुएं हैं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियम के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

6. **सामान्य मूल्य.**—याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 व 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ अन्य संबद्ध देशों (जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जा रहा है) के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए।

नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ थाइलैंड, कोरिया जन. गण. या मलेशिया को उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चुने जाने की परिकल्पना की गई है। हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा इस अधिसूचना में निर्धारित विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इस विकल्प के औचित्य के बारे में टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

थाइलैंड, मलेशिया या कोरिया जन. गण. में सामान्य मूल्य के बारे में याचिकाकर्ता ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय तथा उचित लाभ सहित उत्पाद लागत के अनुमानों पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। 14" तथा 21" समतल के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

7. **निर्यात कीमत.**—याचिकाकर्ता ने डी जी सी आई एंड एस, आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आयात आंकड़ों तथा आई सी डी, दादरी में सूचित आयात संबंधी वास्तविक सूचना के आधार पर प्रस्तावित अवधि में आयात कीमत के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा किया है। 14" तथा 21" समतल के लिए अलग-अलग निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है।

कारखाना द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा तथा निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन प्रहस्तन एवं पत्तन प्रभार हेतु समायोजन का दावा किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

8. **पाटन मार्जिन.**—सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की तुलना 14" तथा 21" (समतल) के लिए अलग-अलग कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। यह विचार किया गया है कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध.**—याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्डों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। आयातों में सापेक्ष और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, वस्तु सूची में वृद्धि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अत्यधिक गिरावट, लाभ की स्थिति से अत्यधिक वित्तीय घाटे, नकद लाभ एवं निवेश पर आय तर्क लाभों का अत्यधिक क्षरण जैसे मापदण्डों से प्रथम दृष्टया सामूहिक एवं संचयी रूप से यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

10. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत.**—और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के उपस्थित होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। प्राधिकारी एतद्वारा कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने और पाटन-रोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, के लिए उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की जांच शुरू करते हैं।

11. **जांच की अवधि (पीओआई).**—वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जुलाई, 2006 से 30 जून, 2007 (12 महीने) तक की है। तथापि, क्षति संबंधी जांच के लिए अवधि 1 अप्रैल, 2004 से जांच अवधि के अंत तक की अवधि शामिल होगी।

12. **सूचना प्रस्तुत करना.**—संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात संबद्ध आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जो वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक हो, निम्नलिखित को सूचित कर सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 240

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिनिधि ग्राहक संगठन, जो पाटन क्षति एवं आकस्मिकता के बारे में जांच के संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को भी अवसर प्रदान किया गया है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच के संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

13. समय सीमा

(क) **सामान्य समय सीमा.**—वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए। तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों को अलग

से लिखा जा रहा है उनके द्वारा उन्हें अस्त्रा से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में दर्ज तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

(ख.) बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के चयन के लिए विशिष्ट समय-सीमा.—जांच के हितबद्ध पक्षकार थाइलैंड, कोरिया जन. गण. य. मलेशिया, जिन्हें इस जांच प्रारंभ अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 5 में किए गए उल्लेख के अनुसार चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, के संबंध में टिप्पणी करने की इच्छा रख सकते हैं। ये टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना.—नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा तो उसके कारण का विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

15. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण.—नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल रखी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया जा सकता है।

16. असहयोग.—यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से बना करता है, अथवा किसी उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING
AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2007

Sub : Initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Cathode Ray Colour Picture Tubes of 14" and 21" (flat) sizes originating in or exported from Malaysia, Thailand, China and Korea RP.

No. 14/8/2006-DGAD.—M/s. Samtel Color Limited has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination

of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Cathode Ray Colour Picture Tubes of 14" and 21" (flat) sizes originating in or exported from Malaysia, Thailand and China (for both 14" and 21") and Korea RP (for 21") and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

2. Product under consideration.—The product under consideration in the present investigations is cathode ray colour picture tubes of 14" and 21" (flat) sizes (i.e., 21" flat type and 14" conventional). Cathode ray colour picture tubes are stated to be manufactured in various sizes. However, the present investigations are only in respect of 14" conventional and 21" (flat) sizes. The products, it has been stated, can be specified by the flatness of their tubes—the bulb-type (including semi flat/full square), the flat tubes and real flat or flat-slim tubes. Finally, they are stated to operate under a frequency of 50, 60 or 100 Hz. These products are mainly applied in colour television sets.

The subject goods falls under Chapter 85 of the Custom Tariff Act, 1975 under subheading No. 8540.11. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Domestic Industry Standing.—The application has been filed by M/s. Samtel Color Limited. The petitioner has provided information relevant to the present investigations. The subject goods are also produced by JCT Electronics Limited, BPL Display Devices Limited and Hotline CPT Limited. Production of the petitioner constitutes more than 50% of Indian production. Production of the petitioner company constitutes a major proportion in Indian production. The Authority after examination, has determined, that the petitioner constitutes domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules *supra*.

4. Countries Involved.—Petition has been filed seeking imposition of anti-dumping duties on imports of the product under consideration from Malaysia, Thailand and China (for both 14" and 21") and Korea RP (for 21"). The countries involved in the present investigation therefore are Malaysia, Thailand and China (for both 14" and 21" Flat) and Korea RP (for 21" Flat) (hereinafter also referred to as subject countries).

5. Like Goods.—The petitioner has claimed that goods produced by domestic industry are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules *supra*.

6. Normal Value.—The petitioner has claimed that China PR should be treated as non-market economy and have determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the anti-dumping rules. The petitioner has submitted that normal value determined for other subject countries (which are being treated market economy countries) may be considered for determination of normal value for China.

In accordance with Para 7 to Annexure I of the Rules, it is envisaged to choose Thailand, Korea RP or Malaysia as an appropriate market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of China PR. Interested parties are hereby invited to comment on the appropriateness of this choice within the specific time limit laid down in this notification.

With regard to normal value in Thailand, Malaysia and Korea RP, petitioner has claimed normal values for the subject goods considering estimates of cost of production including selling, general and administrative overheads and reasonable profit. Normal value has been separately determined for 14" and 21" Flat.

7. Export Price.—Petitioner has claimed export price of the subject goods from the subject countries on the basis of import price in the proposed period, based on transaction wise import data provided by the DGCI & S, IBIS and actual information on imports reported at ICD, Dadri. Export price has been separately determined for 14" and 21" Flat.

Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance and inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of the export price for the subject goods from the subject countries.

8. Dumping Margin.—Normal value and export price have been compared at ex-factory level, separately for 14" and 21" (flat), which shows significant dumping margin in respect of each of the subject countries for each of the product. It is considered that there is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods, are being dumped by exporters from the subject countries.

9. Injury and Causal Link.—Petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury to the domestic industry. Parameters such as increase in imports in absolute terms as also relative to production and consumption in India, significant price undercutting, increase in inventories, significant decline in the market share of the domestic industry, significant deterioration in profits from a situation of profits to significant financial losses, cash profit and return on investment, significant price undercutting, *prima facie*,

collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports.

10. Initiation of Anti-dumping Investigations.—And whereas, the Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

11. Period of Investigation (POI).—The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st July, 2006 to 30th June, 2007 (12 months). However, the period for injury examination would cover periods from 1st April, 2004 to the end of the POI.

12. Submission of Information.—The exporters in the subject countries and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied
Duties, Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

As per Rule 6(5) of Rule *supra*, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and casualty. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

13. Time Limit

(a) General Time Limits.—Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in

accordance with the Rules *supra*.

(b) **Specific time limit for selection of market economy country.**—Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of Thailand, Korea RP and Malaysia which, as mentioned in the Para 5 of this initiation notification, envisaged as a market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the China PR. These comments must be submitted within two weeks from the date of publication of this notification.

14. Submission of Information on Non-Confidential Basis.—In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information,

such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

15. Inspection of Public File.—In terms of Rule 6(7), Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

16. Non-Cooperation.—In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

3985 GI/07-2